



सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शादियों में एक साल तक सोना न खरीदने की अपील ने देशभर में नई बहस छेड़ दी है। वैश्विक तेल संकट, बढ़ते आयात बिल और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को देखते हुए इसे आर्थिक संतुलन की कोशिश माना जा रहा है। वहीं ज्वेलरी कारोबारियों और आम लोगों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या परंपरा और बाजार पर इसका बड़ा असर पड़ेगा।

एक साल तक सोना मत खरीदिए!

PM मोदी की अपील के पीछे छिपी बड़ी आर्थिक चिंता

नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक शादियों के लिए सोना न खरीदने की अपील की।

ज्वेलरी कारोबारियों ने कहा कि इसका असर सर्पि बाजार और छोटे व्यापारियों पर पड़ सकता है।

नरेंद्र मोदी की यह अपील कि लोग एक साल तक शादियों के लिए सोना न खरीदें, देशभर में चर्चा का विषय बन गई है। भारत जैसे देश में, जहां सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि परंपरा, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, वहां ऐसी अपील को असाधारण माना जा रहा है। दरअसल, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वैश्विक तेल संकट और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता दबाव है। मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास की अस्थिरता के कारण कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल है और तेल महंगा होने का सीधा असर



विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है।
ऐसे में सोने का भारी आयात
स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना
सकता है। अर्थशास्त्रियों का
कहना है कि भारत हर साल बड़ी
मात्रा में सोना आयात करता है,
जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है।
अगर तेल और सोना दोनों का
आयात एक साथ महंगा हो जाए,
तो रुपये पर दबाव बढ़ सकता है।
प्रधानमंत्री की अपील को इसी

आर्थिक संतुलन की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इस बयान के बाद ज्वेलरी और कारोबारियों और सरफा बाजार में चिंता बढ़ गई है। कई व्यापारिक संगठनों ने कहा कि सोने की खरीद भारतीय शादी संस्कृति का अहम हिस्सा है और इसका असर लाखों छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। दूसरी ओर, सरकार समर्थकों का

कहना है कि संकट के समय राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। यह मुद्दा अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि जनता प्रधानमंत्री की इस अपील को किस तरह लेती है।

PM मोदी की राष्ट्रव्यापी अपील से बड़ी चिंता



मध्य-पूर्व युद्ध और वैश्विक तेल संकट के बीच नरेंद्र मोदी की राष्ट्रव्यापी अपील ने देशभर में नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से वॉल-फ्रॉम-होम को दोबारा अपनाने, ईंधन की ख़र्च कम करने और एक साल तक सोना ख़रीदने से बचने की अपील की। उनकी इस अपील को कई लोग आने वाले बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी के रूप में देख रहे हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तेल कीमतें लगातार बढ़ती रहें, तो भारत का आयात बिल बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसका असर महंगाई, रुपये की कीमत और आम लोगों के खर्च पर पड़ेगा। सरकार फिलहाल प्रदोल-डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी से बच रही है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना मुश्किल हो सकता है।वॉल-फ्रॉम-होम की अपील ने लोगों को कोरोना महामारी के दौर की याद दिला दी। कई कंपनियों ने पहले ही कर्मचारियों के लिए हाइब्रिड मॉडल पर विचार शुरू कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की बचत होगी और आयात दबाव कम किया जा सकेगा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर हालात इतने गंभीर हैं, तो सरकार को स्पष्ट आर्थिक नोटअप सामने रखना चाहिए। वहीं भाजपा नेताओं ने इस ज़िम्मेदार नेतृत्व का उदाहरण बताया है।आर्थिक जानकारों के अनुसार, भारत फिलहाल संकट की स्थिति में नहीं है, लेकिन वैश्विक हालात तेजी से बदल रहे हैं। अगर मध्य-पूर्व में संघर्ष और बढ़ता है, तो तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सरकार पहले से जनता को तैयार करने की कौशिल्य कर रही है।



फडणवीस का कांग्रेस पर करारा हमला

देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें 'भारतीय राजनीति की सबसे अस्वीकृत वस्तु' बता दिया। महाराष्ट्र में मीडिया से बातचीत के दौरान फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता बार-बार उन्हें नकार चुकी है। उनका यह बयान राहुल गांधी के उस भाषण के बाद आया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की 'सात अपीलों' को आर्थिक विफलता का प्रमाण बताया था। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ने वृत्त जनता की भावनाओं को समझने में विफल रहा है। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को अनवृत्त वृत्त के रूप में देखती है, जबकि राहुल गांधी केवल आलोचना की राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब देश वैश्विक आर्थिक संकट और तेल कीमतों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब विपक्ष को सहयोग की राजनीति करनी चाहिए, कि केवल नकारात्मक बयान देने चाहिए। राजनीतिक हलकों में फडणवीस का यह बयान काफी चर्चा में है। कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए व्यक्तिगत हमले कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक दबाव जैसे मुद्दों पर सरकार के पास जवाब नहीं है, इसलिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना पड़ा है।

बंगाल में सत्ता बदलते ही बड़ा ऐक्यान

सुवेन्दु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले

सुर्वेदु अधिकाऱी ने मुख्यमन्त्री बनने के बाद पहली बार नबन्ना भवन में कैबिनेट बैठक की और कई बड़े फैसलों की घोषणा कर दी। भाजपा के पहले मुख्यमन्त्री के रूप में पद संभालने वाले अधिकाऱी ने दावा किया कि बंगाल में पहली बार “भयमुक्त और हिंसामुक्त चुनाव” हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी सरकार “सभी के लिए काम करेगी।” कैबिनेट बैठक में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, भ्रष्टाचार की जांच, निवेश बढ़ाने, सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े छह महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमन्त्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान प्रशासनिक ढांचे में कई खामियां थीं, जिन्हें अब सुधारा जाएगा। उन्होंने राज्य में उद्योग निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति लाने का भी संकेत दिया। राजनीतिक रूप से यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई है। अधिकाऱी ने कहा कि बंगाल को “राजनीतिक हिंसा की संस्कृति” से बाहर निकालना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब बिना राजनीतिक भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंचेगा। विपक्षी दलों ने हालांकि भाजपा सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि रविश्लेषकों के अनुसार, सुर्वेदु अधिकाऱी की पहली कैबिनेट बैठक



केवल प्रशासनिक शुरुआत नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। भाजपा बंगाल में अपनी सरकार को "परिवर्तन मॉडल" के रूप में पेश करना चाहती है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने वादों को किस हद तक जमीन पर उतार पाती है। **आजपा** में "नई प्रशासनिक संस्कृति" की शुरुआत हो चुकी है।

सुवेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बड़ा खुलासा

सूवेदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग एक डिजिटल पेमेंट से मिला है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने हावड़ा के बल्ली टोल प्लाजा को पार करते समय यूपीआई के जरिए भुगतान किया था, जिसके बाद उनकी लोकेशन ट्रैक कर बिहार के बक्सर तक पहुंचा गया। जांच में सामने आया कि हत्या के बाद आरोपी तेजी से पश्चिम बंगाल छोड़कर बिहार की ओर भागे थे। लेकिन रास्ते में किए गए डिजिटल भुगतान ने पुलिस को उनकी गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड दे दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष टीम ने बिहार के बक्सर जिले में छापेमारी की और तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया। बक्सर के पुलिस अधीक्षक

शुभम आर्य ने पुष्टि की कि बंगाल पुलिस की टीम लगातार इलाके में जांच कर रही है। यह मामला इसलिए भी संवेदनशील हो गया है क्योंकि मृतक मुख्यमंत्री के बेटे की माने जाते थे। पुलिस अब हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश, व्यक्तिगत दुश्मनी और आर्थिक लेनदेन समेत कई पहलुओं की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों के मोबाइल डेटा और बैंक ट्रान्जेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केस दिखाता है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम अपराधों में कितना बड़ा हथियार बन चुका है। पहले जहां अपराधी नकदी के जरिए पहचान छिपा लेते थे, वहीं अब डिजिटल लेनदेन उनकी लोकेशन और गतिविधियों का रिकॉर्ड छोड़ देता है। राजनीतिक तौर पर भी इस हत्या



ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। भाजपा नेताओं ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताया है, जबकि विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आने वाले दिनों में जांच और खुलासे इस मामले को और बड़ा बना सकते हैं।

राहुल गांधी ने PM मोदी की '7 अपीलों' को बताया आर्थिक संकट का संकेत

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया "सात अपीलें" पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये देशवासियों के लिए उपदेश नहीं, बल्कि सरकार की आर्थिक नाका के सबूत हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश आर्थिक दबाव में है और अब जनता से त्याग की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होती, तो सरकार को लोगों से पेट्रोल कम इस्तेमाल करने, सोना न खरीदने या खचक न घटाने जैसी अपीलें नहीं करनी पड़तीं। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार तेल कीमतों, बैरोजगारी और महंगाई पर नियंत्रण पाने में विफल रही। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य-पूर्व संकट का असर पूरी दुनिया पर है, लेकिन भारत में स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर लग रही है क्योंकि सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की। कांग्रेस नेताओं ने इस

मुझे को "आर्थिक आपात संकेत" बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता पर बोझ डालकर संकट से निकलने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को गैर-जिम्मेदाराना बताया है। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपीलें राष्ट्रीय हित में हैं और देश को वैश्विक संकट के समय सामूहिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पार्टी नेताओं ने कहा कि तेल संकट अस्थायी है और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है।



वारंगल में मोदी-रेवंत की राजनीतिक जुगलबंदी विकास के मंच पर NDA का न्योता

तेलंगाना के वारंगल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को हल्के-फुल्के अंदाज में NDA में आने का न्योता देकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। रेवंत रेड्डी ने मनमोहन सिंह सरकार के दौरान गुजरात को मिले सहयोग का हवाला देते हुए तेलंगाना के लिए भी वैसा ही समर्थन मांगा। इस दौरान पीएम मोदी ने 9,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और देश के पहले पूर्ण PM MITRA टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन भी किया।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी से मजाक में NDA के साथ आने को कहा। दरअसल पीएम राज्य में 9,400 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का इन्फॉर्मेशन करने पहुंचे थे। पीएम ने यहां हल्के-फुल्के अंदाज में रेड्डी से कहा कि केंद्र सरकार ने 10 साल में गुजरात को जो दिया, मैं तेलंगाना को देने के लिए तैयार हूं। मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा करते ही आपको अभी जो सरकार से मिल रहा है, वह आधा हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझसे ही जुड़ो। हालांकि पीएम ने ये बातें तेलंगाना सीएम की एक सिफारिश के चलते कहीं। इसमें रेवंत ने अपने भाषण में पीएम से कहा कि जिस तरह मनमोहन सरकार में गुजरात का विकास हुआ, उसी तरह तेलंगाना का भी



विकास हो। रेवंत रेड्डी ने कहा, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तब मोदी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 10 साल में 'गुजरात मॉडल' को साकार किया। इसी तरह, तेलंगाना के लोगों को उम्मीद है कि अगले 10 साल में मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए तेलंगाना विकास मॉडल भी साकार होगा। जिस तरह मनमोहन सिंह ने गुजरात का समर्थन किया था, उसी तरह हम तेलंगाना के विकास में समर्थन करने का अनुरोध करते हैं। रेवंत ने यह भी कहा कि जहां एक ओर मोदी भारत का विकास चाहते हैं, वहीं उन्हें तेलंगाना को

भी साथ लेकर चलना चाहिए। तेलंगाना के विकास के लिए, कृपया दो घंटे का समय निकालें, ताकि हम आपके सामने अपने विकास प्रस्ताव पेश कर सकें। रेवंत की बात का जवाब देते हुए पीएम ने कहा- जो कुछ भी केंद्र सरकार (पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में) ने गुजरात को 10 साल में दिया (जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे), मैं भी आपको वह सब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन तब राज्य के पास उतना भी नहीं बचेगा, जितना उसे अभी केंद्र से मिल रहा है और आप अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। बेहतर

यही है कि आप मेरे साथ आ जाएं। पीएम मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में PM MITRA पार्क का भी इन्फॉर्मेशन किया। इसे काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। करीब 1,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित यह भारत का पहला पूरी तरह से काम करने वाला PM MITRA पार्क है। यह भारत सरकार के '5F' विजन को साकार करता है - Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign (यानी खेत से फाइबर तक, फैक्ट्री से फैशन तक और फैशन से विदेश तक)।

विदेश में खरीदारी अब भारतीयों के लिए पड़ रही मंहगी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

विदेश में खरीदारी को लेकर भारतीय उपभोक्ताओं के बीच नई बहस शुरू हो गई है। डील्स धमाका मंच के संस्थापक विनीत के के हालिया बयान के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है। उनका कहना है कि अब अमेरिका में खरीदारी भारतीयों के लिए पहले जैसी सस्ती और फायदेमंद नहीं रह गई है। रुपये की कमजोरी और वैश्विक महंगाई ने विदेशी बाजारों में खरीदारी का गणित काफी बदल दिया है। विनीत के ने अपने हालिया अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस बार अमेरिका में उनका खरीदारी बिल सामान्य की तुलना में केवल लगभग 30 प्रतिशत ही रहा। उनके अनुसार यह साफ संकेत है कि भारतीय उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना है। फिलहाल भारतीय मुद्रा लगभग 95 रुपये प्रति डॉलर के आसपास पहुंच गई है, जिससे विदेशी खरीदारी पहले की तुलना में काफी मंहगी हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक महंगाई ने अमेरिका समेत कई देशों में सामान की कीमतें बढ़ा दी हैं। यही कारण है कि अब वहां से इलेक्ट्रॉनिक सामान, फैशन उत्पाद या रोजमर्रा की चीजें खरीदने में पहले जैसा लाभ नहीं मिल रहा। विनीत के ने भारतीय उपभोक्ताओं को सलाह दी कि मंहगे उपकरण, खासकर स्मार्टफोन और गैजेट्स, अब भारत में खरीदना अधिक समझदारी हो सकती है क्योंकि कीमतों का अंतर काफी कम हो गया है। भारतीय उपभोक्ता विदेश की बजाय घरेलू बाजार को अधिक व्यावहारिक विकल्प मानने लगे हैं।

हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा की पार्टी घोषणापत्र को लागू करने को प्राथमिकता देगी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

असम के भावी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि 12 मई को शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार पार्टी के घोषणापत्र को लागू करने को प्राथमिकता देगी। पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद हम पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। हमारा लक्ष्य अपने घोषणापत्र को लागू करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 मई को गुवाहाटी पहुंचने की उम्मीद है, जहां वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति और पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री आज रात गुवाहाटी पहुंचेंगे। कल सुबह 11 बजे असम की नई सरकार शपथ लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समारोह में शामिल होंगे। हमारी पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं सहित कई लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इससे पहले 11 मई को असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की ओर से हिमंता बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया। राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरमा को इस पद पर नियुक्त किया। सरमा 12 मई, 2026 को सुबह 11:40 बजे



गुवाहाटी के खानापारा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। 11 मई को सरमा ने राज्यपाल आचार्य से मुलाकात की और असम में भाजपा और एनडीए दोनों विधानसभा दलों के नेता चुने जाने के बाद औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने X पर एक पोस्ट में अपनी नियुक्ति की पुष्टि करते हुए बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। विधानसभा को संबोधित करते हुए शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी।



PM KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA

THE WORLD'S LARGEST DBT SCHEME FOR THE FARMERS - A DIGITAL MARVEL

SCAN, ENTER & CONNECT

- KNOW ABOUT EKYC
- KNOW YOUR STATUS
- 📱 PM KISAN MOBILE APP






चीन की यात्रा पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा की तारीख भी सामने आ गई है। सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप की ये चीन यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है और दुनिया में अमेरिकी टैरिफ का संकट भी चल रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की यात्रा से पहले भविष्यवाणी की थी। ट्रंप ने कहा था कि चीन पहुंचने पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्हें गले लगाएंगे। हालांकि, जानकारों की मानें तो अमेरिकी टैरिफ, ईरान में जंग और चीन व अमेरिका के बीच कई क्षेत्रों में टकराव को देखते हुए गर्मजोशी की संभावना कम है। हालांकि, ट्रंप ने कई बार कहा है कि वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने को लेकर आशान्वित हैं और उन्हें लगता है कि शी जिनपिंग भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। इससे पहले ट्रंप ने चीन को टारगेट किया था और कहा था कि ईरान को हथियार बेचने वाले देशों से आने वाले सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि, इसके कुछ ही दिन बाद ट्रंप ने



कहा था कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने ईरान को हथियार भेजने की बात से इनकार किया है। आपको बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2017 में चीन की यात्रा की थी। ये यात्रा काफी भव्य थी और चीन ने इसे राजकीय यात्रा से भी बढ़कर करार दिया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले मार्च महीने के आखिर में चीन की यात्रा करने वाले थे। हालांकि, ईरान से जारी जंग के बीच उनकी इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। ट्रंप और शी की अक्टूबर में दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी।

हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह पसरा सन्नाटा

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पिछले 24 घंटे में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी जहाज गुजर नहीं पाया है। अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब इस रास्ते पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले यहां रोजाना औसतन 130 से ज्यादा जहाज गुजरते थे। इसके बंद होने से अब तेल की आपूर्ति, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के हवाले से आरटी ने यह जानकारी दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट से टैंकर रोजाना करोड़ों बैरल तेल लेकर निकलते थे। लेकिन अब जहाजों का आना-जाना बंद हो गया है। इस बीच खाड़ी के देश एकजुट होकर ईरान पर दबाव बना रहे हैं। कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष राजनयिकों ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि हॉर्मुज में पहले जैसा यातायात फिर से शुरू होना चाहिए। सऊदी अरब और कुवैत अमेरिका के साथ मिलकर एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में ईरान से मांग की गई है कि वह जहाजों पर हमले बंद करे, गैरकानूनी टोल वसूलना छोड़े और समुद्र में बिछाए गए माइन्स की सारी जानकारी दे। साथ ही मानवीय



सहायता के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर बनाने में भी ईरान को सहयोग करना होगा। इन देशों का कहना है कि इससे खाद्यान्न, उर्वरक और जरूरी सामान आसानी से पहुंच सकेगा। उधर, अमेरिका सेना अब भी ईरान को सबक सिखाने के लिए हॉर्मुज में डेरा डाले बैठी हुई है। अमेरिका की ईरान पर लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी अब भी पूरी तरह से लागू है। इस बीच, अमेरिकी सेना ने जानकारी दी है कि उनकी नौसेना ने 13 अप्रैल से अब तक कुल 58 व्यापारिक जहाजों को रास्ता बदलने को

मजबूर किया है, जबकि 4 जहाजों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है। पहले यहां रोजाना औसतन 130 से ज्यादा जहाज गुजरते थे। इसके बंद होने से अब तेल की आपूर्ति, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के हवाले से आरटी ने यह जानकारी दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट से टैंकर रोजाना करोड़ों बैरल तेल लेकर निकलते थे। लेकिन अब जहाजों का आना-जाना बंद हो गया है।



संपादक की कलम से

भारत में लंबे समय से लंबित जातीय जनगणना एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। आगामी जनगणना में जाति आधारित आंकड़े जुटाने की चर्चा ने राजनीति, समाज और प्रशासन—तीनों स्तरों पर नई बहस को जन्म दिया है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि 2026-27 की जनगणना में जातिगत आंकड़ों को शामिल किया जा सकता है। दरअसल, भारत जैसे विविधताओं वाले देश में केवल जनसंख्या गिनना पर्याप्त नहीं है। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की वास्तविक तस्वीर सामने लाने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि किस वर्ग की स्थिति क्या है। आज भी शिक्षा, सरकारी नौकरियों, स्वास्थ्य सुविधाओं और आर्थिक अवसरों में जातीय असमानता स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे में जातीय जनगणना नीति निर्माण को अधिक यथार्थवादी बना सकती है। हालांकि इस मुद्दे का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आशंका यह है कि जातीय आंकड़े राजनीतिक दलों के लिए केवल वोट बैंक की राजनीति का माध्यम न बन जाएं। भारत पहले ही जातीय धुवीकरण की चुनौती झेल रहा है। यदि आंकड़ों का उपयोग सामाजिक समरसता बढ़ाने के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए हुआ, तो समाज में विभाजन और गहरा सकता है। यह भी सच है कि स्वतंत्रता के बाद सरकारों ने जाति आधारित आंकड़ों को सीमित रखने की कोशिश इसलिए की थी ताकि समाज धीरे-धीरे जातीय पहचान से ऊपर उठ सके। लेकिन सात दशकों बाद भी यदि आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कल्याणकारी योजनाओं का आधार जाति ही है, तो अद्यतन आंकड़ों की आवश्यकता को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जातीय जनगणना केवल संख्या गिनने तक सीमित रहेगी या इससे सामाजिक न्याय की दिशा में वास्तविक सुधार होंगे? यदि आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संसाधनों का अधिक न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाए, तो यह लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है। लेकिन यदि इसका उपयोग केवल चुनावी समीकरण साधने के लिए हुआ, तो यह समाज को और अधिक खंडित कर देगा। भारत को आज ऐसी राजनीति की जरूरत है जो जाति की वास्तविकताओं को स्वीकार करे, लेकिन समाज को स्थायी रूप से जातीय खांचों में कैद न करे। जातीय जनगणना का उद्देश्य सामाजिक समानता होना चाहिए, न कि सामाजिक विभाजन। यही इस बहस की सबसे बड़ी कसौटी है।

बंगाल की भाजपा की पहली कैबिनेट बैठक शुभेंदु अधिकारी ने बड़े फैसलों की घोषणा की

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक सुधार, सीमाई सुरक्षा, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसलों की घोषणा की। नवान्न में आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब 'सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार' के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है और पश्चिम बंगाल को भाजपा शासित अन्य राज्यों की विकास नीति के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संविधान निर्माता बीआर अंबेडकर के 'जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सरकार' के सिद्धांत पर काम करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डर बाहर, भरोसा अंदर' संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि नई सरकार लोगों की सुरक्षा, विश्वास और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

पहली कैबिनेट में शुभेंदु सरकार ने लिए कई अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में सबसे अहम निर्णयों में सीमाई सुरक्षा को लेकर बीएसएफ को आवश्यक जमीन सौंपने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का फैसला शामिल है। मुख्यमंत्री ने भूमि एवं राजस्व विभाग तथा मुख्य सचिव को अगले 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने अवैध घुसपैठियों के हित में केंद्र और अदालतों के निर्देशों की अनदेखी की थी।

सरकार ने राज्य को आधिकारिक रूप से आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का भी निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समझौते जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, पीएम श्री, विश्वकर्मा योजना, बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना समेत कई केंद्रीय योजनाओं को राज्य में तेजी से लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई। जिला अधिकारियों को सभी लंबित आवेदनों को शीघ्र केंद्र को भेजने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय बाद पश्चिम



बंगाल में 'भयमुक्त, रक्तपात रहित और निष्पक्ष चुनाव' संपन्न हुआ है। इसके लिए मतदाताओं, प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद दिया गया। साथ ही उन्होंने भाजपा के 321 राजनीतिक शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई। उन्होंने आगे कहा 'सभी मतदाताओं, चुनाव आयोग (ईसी), केंद्रीय बलों, पुलिस, पर्यवेक्षकों और सभी राजनीतिक दलों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही हमारे संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 321 व्यक्तियों के संबंध में कहा कि यदि उनके परिवार चाहें, तो सरकार जांच शुरू करेगी।' सरकारी नौकरियों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा भी बढ़ाई

प्रशासनिक सुधारों के तहत आईएसएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण प्रणाली से जोड़ने का फैसला लिया गया

है। राज्य में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अनुरूप प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह समायोजित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। युवाओं को राहत देते हुए सरकारी नौकरियों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने जनगणना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के 16 जून 2025 के निर्देश को लागू नहीं किया था, जिसे वर्तमान सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य की मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, लेकिन उन्हें पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी मृत व्यक्ति, गैर-भारतीय या अवैध व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

उदयनिधि स्टालिन बने विपक्ष के नेता

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

तमिलनाडु विधानसभा की 17वीं बैठक सोमवार, 11 मई को होगी। सुबह 9.30 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी। इसी दौरान सभी नए विधायक शपथ लेंगे। अगले दिन विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं, उदयनिधि स्टालिन को पहले ही विपक्ष का नेता चुना जा चुका है। वह डीएमके विधायक दल के नेता भी हैं। टीवीके नेता एमवी करुप्पैया एमवी को कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की उपस्थिति में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलैंकर के सामने तमिलनाडु विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। इससे पहले सुबह 10 बजे विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अभिनेता से राजनेता बने विजय ने ऐतिहासिक चुनावी जीत हासिल करने के बाद राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके तुरंत बाद चेन्नई के फोर्ट जॉर्ज स्थित तमिलनाडु सचिवालय में आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया। राज्यपाल अलैंकर ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विजय और उनके मंत्रिमंडल के नौ मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पदभार ग्रहण करने के बाद, उन्होंने चेन्नई के पेरियार थिदल स्थित थंथाई पेरियार ईवी



रामास्वामी स्मारक पर समाज सुधारक ईवी रामास्वामी (पेरियार) को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष के. वीरमणि से भी मुलाकात की। 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने वर्चस्व को समाप्त कर दिया। 'थलपति' के नाम से मशहूर विजय के उदय की

तुलना पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेता एमजी रामचंद्रन से की जा रही है। राज्य विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का पदभार संभालने से पहले विजय ने तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अपना इस्तीफा दे दिया और विधानसभा के प्रधान सचिव के. श्रीनिवासन को पत्र भेज दिया। राज्य विधानसभा सचिवालय ने बताया कि उन्होंने पेरम्बूर सीट बरकरार रखी है।

चुनावों में मिली करारी हार एआईएडीएमके के भीतर गहरी दरार

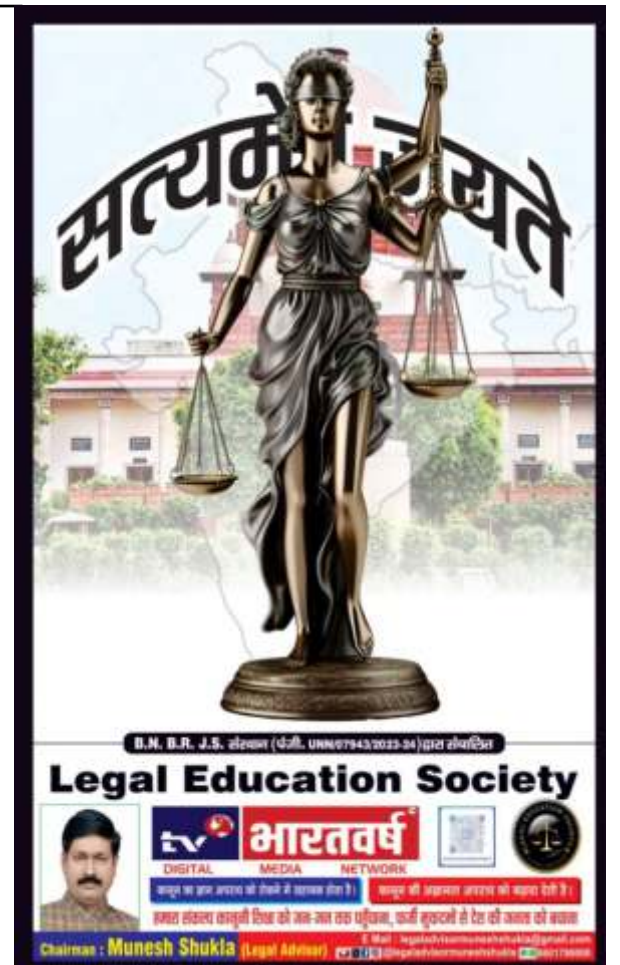
टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

हाल ही में हुए चुनावों में मिली करारी हार ने एआईएडीएमके (AIADMK) के भीतर गहरी दरार पैदा कर दी है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी टीवीके (TVK) को समर्थन देने के सवाल पर पार्टी के विधायक आपस में बंट गए हैं। इसके साथ ही पार्टी के मुखिया एडम्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) के खिलाफ भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आंकड़ों की बात करें तो एआईएडीएमके ने कुल 234 सीटों में से 167 पर चुनाव लड़ा था। हालांकि, पार्टी को केवल 47 सीटों पर ही सफलता मिल सकी। इस खराब चुनावी प्रदर्शन के बाद पार्टी महासचिव पलानीस्वामी ने विधायकों के साथ कई बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान पार्टी के अंदर दो अलग-अलग विचार सामने आए। पार्टी सूत्रों के अनुसार, एक गुट सरकार बनाने के लिए टीवीके को किसी भी तरह का समर्थन देने के सख्त खिलाफ है। वहीं, दूसरा गुट चाहता है कि अभिनेता विजय की पार्टी को बाहर से समर्थन दिया जाए। इस खींचतान के बीच कुछ विधायकों ने सीधे तौर पर मांग की है कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए पलानीस्वामी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी में बढ़ते असंतोष का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सी वी शनमुगम और एस पी वेलुमणि जैसे कदावर नेता और पूर्व मंत्री बैठकों में नहीं



पहुंचे। उनके समर्थक विधायकों ने भी इन बैठकों से दूरी बनाए रखी। पार्टी के जानकारों का कहना है कि शनमुगम और वेलुमणि का गुट टीवीके को समर्थन देने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इस बीच एआईएडीएमके के पूर्व नेता के सी पलानीसामी ने इस स्थिति पर कहा कि पार्टी में विभाजन साफ दिख रहा है। कई विधायक नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पलानीस्वामी पद पर बने रहते हैं, तो

संभव है कि कुछ विधायक टीवीके के साथ चले जाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि पार्टी की एकता और अगले चुनाव की तैयारी के लिए पलानीस्वामी को खुद पद छोड़ देना चाहिए। दूसरी ओर, राजनीतिक विश्लेषक सत्यालय रामकृष्णन ने कहा कि नेताओं को आपसी मतभेद बातचीत से खत्म करने चाहिए।



सीईयूटी यूजी 2026 परीक्षा 11 मई से शुरू हो गई 15.7 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था

देशभर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आयोजित होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईयूटी यूजी 2026 परीक्षा आज 11 मई से शुरू हो गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यह परीक्षा 31 मई 2026 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मोड में आयोजित की जाएगी. इस बार परीक्षा के लिए करीब 15.7 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

यह परीक्षा भारत के साथ-साथ विदेश में भी आयोजित की जा रही है. पहले दिन की पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक चलेगी. ऐसे में एनटीए ने परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए जरूरी गाइडलाइन भी जारी की है.

दो शिफ्ट में हो रही परीक्षा

सीईयूटी यूजी 2026 परीक्षा कुल 2 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है. परीक्षा की पहली शिफ्ट 9 बजे से दोपहर दो 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 3 से 6 बजे तक होगी. एनटीए के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 1 से 2 घंटों पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना चाहिए. गेट बंद होने के बाद किसी भी छात्र को एंट्री नहीं दी जाएगी.

क्या है परीक्षा पैटर्न?

सीईयूटी यूजी परीक्षा 13 भाषाओं, 23 डोमेन सबजेक्ट्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आयोजित की जा रही है. प्रत्येक विषय में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और हर विषय में 60 मिनट का समय मिलेगा. भाषा सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन आधारित प्रश्न होंगे, जबकि डोमेन सबजेक्ट्स के सवाल एनसीईआरटी कक्षा 12 के सिलेबस पर आधारित होंगे. जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक मैथ्स से जुड़े सवाल



पूछे जाएंगे.

स्टूडेंट्स क्या लेकर जा सकते हैं एग्जाम सेंटर पर?

एनटीए की गाइडलाइन के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर कई जरूरी डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे. इनमें सीईयूटी यूजी 2026 की एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक वैलिड फोटो, आईडी प्रूफ और दो पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. इसके अलावा छात्र ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल और ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन भी साथ ले जा सकते हैं. पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को अपना प्रमाण पत्र साथ रखना होगा. डायबिटीज से पीड़ित छात्रों की जरूरी दवाइयां खाने-पीने की चीज

ले जाने की अनुमति भी दी गई है.

किन चीजों पर है पूरी तरह रोक?

परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा नोट्स, किताबें, लिखित सामग्री, बैग, पर्स, बेल्ट, कप, गॉगल्स और बड़ी ज्वेलरी की अनुमति नहीं होगी. नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार की एंट्री रोकी जा सकती है. इस कोड को लेकर क्या है नियम?

एनटीए ने छात्रों को हल्के और साधारण कपड़े पहनकर आने की सलाह दी है. बड़े बटन, ज्यादा पॉकेट वाले कपड़े और भारी एक्सेसरीज से बचने को कहा गया है.

सामान्य जूते-चप्पल और लो हील वाले फुटवियर पहनने की अनुमति होगी. धार्मिक आस्था से जुड़ी चीजें जैसे कलावा पहनने की छूट दी गई है, लेकिन उम्मीदवारों को जांच प्रक्रिया के लिए समय से पहले पहुंचना होगा. सीटिंग और रिपोर्टिंग से जुड़े नियम

परीक्षा हॉल में छात्रों को रोल नंबर के आधार पर सीट अलॉट की जाएगी और उन्हें अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठना होगा. परीक्षा शुरू होने से करीब 30 मिनट पहले एंट्री गेट बंद कर दिए जाएंगे. ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वह एडमिट कार्ड पर दिए गए सेंटर का पता और शिफ्ट टाइमिंग पहले ही चेक कर लें ताकि अंतिम समय में परेशानी न हो.

भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख जानें पढ़ाई से लेकर सैलरी तक सबकुछ

देश की समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी अब एक नए हाथों में जाने वाली है. वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख (Chief of Naval Staff) नियुक्त किया गया है. वे 31 मई 2026 को अपना कार्यभार संभालेंगे. अभी वे मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ हैं. मौजूदा नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी 30 मई को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद यह जिम्मेदारी स्वामीनाथन को सौंपी जाएगी. कृष्णा स्वामीनाथन का जन्म बेंगलुरु में हुआ था. उनके पिता डी. स्वामीनाथन और माता शांता स्वामीनाथन दोनों शिक्षक थे. यानी घर का माहौल शुरू से ही पढ़ाई और अनुशासन से जुड़ा हुआ था. उन्होंने अपनी शुरूआती पढ़ाई बेंगलुरु के मशहूर Bishop Cotton Boys' School से की. इसके बाद वे Sainik School, Bijapur में पढ़े, जहां से उनके अंदर सेना और अनुशासन की नींव और मजबूत हुई. आगे चलकर उन्होंने नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA), पुणे से अपनी उच्च सैन्य शिक्षा पूरी की. यहीं से उनका सफर भारतीय नौसेना की ओर बढ़ा. दुनिया के बड़े सैन्य संस्थानों से मिली ट्रेनिंग कृष्णा स्वामीनाथन सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी उच्च सैन्य प्रशिक्षण ले चुके हैं. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के जॉइंट सर्विसेज कमांड एन्ड स्टाफ कॉलेज श्रीवेनहम से पढ़ाई की है. इसके अलावा उन्होंने College of Naval Warfare, Karanja और United States Naval War College से भी महत्वपूर्ण सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया. 1987 में शुरू हुआ नौसेना का सफर वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था. इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपने काम से एक अलग पहचान बनाई. वे संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते हैं.

पैट कर्मिस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड पाकिस्तान के खिलाफ हुए बाहर

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का ऐलान अगली सीरीज के लिए कर दिया गया है। खास बात ये है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी बाहर रहने वाले हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने न केवल पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम घोषित की है, बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान कर दिया है। इन दोनों टीमों में काफी अंतर देखने के लिए मिल रहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम के तीन तेज गेंदबाजों को इससे बाहर रखा गया है। खास बात ये है कि पैट कर्मिस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड इस टीम में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कुछ युवा और नए खिलाड़ियों का मौका दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर टीम के खिलाड़ी लियाम स्कॉट और ओली पीक को इस टीम में मौका दिया है। साथ ही कुछ पुराने भुला दिए गए प्लेयर्स को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच



इसी महीने के आखिर से तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला 30 मई को खेला जाएगा। माना रहा है कि इसी सीरीज से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम अपने वनडे विश्व कप 2027 की तैयारियों का शुरू करने जा रही है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी, जहां तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

विनेश फोगाट वापसी करने से पहले मुश्किलों में घिरी WFI ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

आखिरी गेंद पर RCB का धमाका

मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ उम्मीदों को बड़ा झटका

आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया मुकाबला इस सीजन के सबसे रोमांचक मैचों में शामिल हो गया. रायपुर की चुनौतीपूर्ण पिच पर दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिर में (RCB) ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज कर मुंबई इंडियंस को टूर्नामेंट से लगभग बाहर कर दिया. 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही. शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद टीम दबाव में नजर आई, लेकिन अनुभवी ऑलराउंडर कृणाल पांड्या ने शानदार पारी खेलते हुए टीम को संभाला. उन्होंने 73 रनों की अहम पारी खेलकर मुकाबले को आखिरी ओवर तक पहुंचाया. मुंबई इंडियंस की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 19वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन दिए. इसके बाद मैच पूरी तरह मुंबई के पक्ष में दिखाई दे रहा था. हालांकि असली सर्पेस आखिरी ओवर को लेकर था. सभी को



उम्मीद थी कि कप्तान सूर्याकुमार यादव अनुभवी या भरोसेमंद गेंदबाज को जिम्मेदारी देंगे, लेकिन उन्होंने युवा ऑलराउंडर राज अंगद बावा पर भरोसा जताया. यह फैसला आखिरकार मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ गया. आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने दबाव में शानदार बल्लेबाजी करते हुए महत्वपूर्ण रन बटोरे. अंतिम गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने आरसीबी को यादगार जीत दिला दी. भुवनेश्वर की इस छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया.

भुवी ने न केवल गेंद से कमाल का प्रदर्शन करते हुए, जबरदस्त छक्का लगाकर सबको चौंका दिया

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के एक रोमांचक मैच में आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस मैच के हीरो भुवनेश्वर कुमार रहे। भुवी ने न केवल गेंद से कमाल का प्रदर्शन करते हुए चार अहम विकेट चटकाए, बल्कि लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच के आखिरी तनावपूर्ण पलों में एक जबरदस्त छक्का लगाकर सबको चौंका दिया। इस उम्दा प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। उनके इस प्रदर्शन ने अंबाती रायडू और दीपदास गुप्ता को भी अपना मुरीद बना लिया। उन्होंने भुवी की तारीफ करते हुए कहा कि भुवी अब 10 साल पहले जैसे थे, वैसे नजर आ रहे हैं। आरसीबी को आखिरी तीन गेंदों पर 9 रन की दरकार थी और वह 8 विकेट गंवा चुकी थी। इसी बीच भुवनेश्वर ने राज अंगद बावा की गेंद पर पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़ दिया, जिससे

मैच पूरी तरह से बेंगलुरु के पक्ष में चला गया। यह एक बहुत ही खास पल था, क्योंकि भुवी ने इससे पहले IPL में आखिरी छक्का 2016 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के खिलाफ लगाया था। प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिलने के बाद भुवनेश्वर ने माना कि उनके लिए विकेट लेने से ज्यादा मायने वह छक्का रखता है। उन्होंने कहा कि वह छक्का, यकीनन! क्योंकि मैंने गेंदबाजी तो कई बार की है। मैंने पहले भी कुछ विकेट लिए हैं। लेकिन हां, छक्का लगाना ही वह चीज है, जिसका मैंने सबसे ज्यादा मजा लिया। भुवनेश्वर ने इस बारे में भी ईमानदारी से बात की कि 36 साल की उम्र में भी वह इतने ऊंचे स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कैसे कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि जो चीज मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, वह अनुशासन है। ईएसपीएल क्रिकेटफंडो पर अंबाती रायडू और



दीपदास गुप्ता ने भुवी की जमकर तारीफ की। गुप्ता ने कहा कि उनमें कोशल की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने वह लय फिर से हासिल कर ली है, जो दस साल पहले थी। एमआई के खिलाफ गेंद को छोड़ने का उनका तरीका सचमुच बहुत अच्छा था।

शादी की शर्त ने मचाया बवाल

अपर कास्ट या फिर 80 लाख की कमाई जरूरी

क्या आज भी शादी में प्यार से ज्यादा जाति और पैसा मायने रखते हैं? हाल ही में सामने आई एक घटना ने इसी सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है। एक पढ़ी-लिखी और सफल महिला ने अपनी शादी के लिए ऐसी शर्त रख दी, जिसने आधुनिक सोच पर सवाल खड़े कर दिए- या तो दूल्हा 'उच्च जाति' का हो, वरना उसकी कमाई 80 लाख रुपये सालाना होनी चाहिए। इस एक शर्त ने दिखा दिया कि आज भी समाज में जाति और स्टेटस की सोच कितनी गहराई से जुड़ी हुई है, भले ही हम खुद को कितना भी प्रगतिशील क्यों न मान लें।

कहानी एक 32 साल की महिला की है, जो अपना खुद का फैशन



बिजनेस चलाती है। वह एक अच्छे और पढ़े-लिखे परिवार से आती है। उसके पिता आईपीएस अधिकारी हैं और मां एक टीचर हैं। यानी बाहर से देखने पर वह एक आधुनिक और प्रगतिशील सोच वाले परिवार की लगती है। लेकिन जब बात शादी की आई, तो उसने दूल्हे के लिए एक खास शर्त रखी। ①

3 लाख महीना भी पड़ रहा कम

कपल ने महंगाई के डर से चुना 'नो किड्स' फॉर्मूला

आज के समय में बढ़ती महंगाई और ऊंचे खर्चों ने लोगों की जिंदगी के बड़े फैसलों को भी बदल दिया है। जहां पहले शादी के बाद बच्चा होना एक सामान्य बात मानी जाती थी, वहीं अब कई कपल इस पर दोबारा सोच रहे हैं।

गुरुग्राम के एक कपल ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया है, अच्छी खासी कमाई होने के बावजूद उन्होंने बच्चा न करने का निर्णय लिया, और इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गुरुग्राम में रहने वाले एक दंपति ने बच्चा न करने का फैसला लिया है, और इसकी वजह है बढ़ती महंगाई और खर्च। इस दंपति की सालाना कमाई करीब 36 लाख रुपये है, जो सुनने में काफी अच्छी लगती है। पति हर महीने लगभग 2 लाख



रुपये कमाते हैं और पत्नी 1 लाख रुपये कमाती हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि वे अभी बच्चे का खर्च नहीं उठा सकते। इस बात को उनके रिश्तेदार हर्ष गुप्ता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यह मुद्दा चर्चा में आ गया। उन्होंने बताया कि कागजों पर तो यह दंपति आर्थिक रूप से मजबूत लगता है, लेकिन असल जिंदगी में खर्च इतने ज्यादा हैं कि वे

परिवार बढ़ाने से बच रहे हैं। कपल का कहना है कि गुरुग्राम जैसे शहर में एक अच्छा घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि वे एक ठीक-ठाक 1BHK फ्लैट भी नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसे में उनका सवाल है कि जब वे खुद के लिए सही जगह नहीं ले पा रहे, तो बच्चे के लिए बेहतर माहौल कैसे देंगे। इसके अलावा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बहुत ज्यादा है। प्राइवेट स्कूलों की फीस हर महीने करीब 35,000 से 40,000 रुपये तक हो सकती है, जो उनके लिए उनके लिए संभालना मुश्किल है। यही कारण है कि उन्होंने अभी बच्चा न करने का फैसला लिया है। आजकल ऐसे कई शहरी कपल हैं, जो डबल इनकम, नो किड्स यानी DINK लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। ②

दिल्ली मेट्रो की लड़ाई वायरल, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

बहस के बाद लड़की ने जड़ा बुजुर्ग को थप्पड़

आए दिन दिल्ली मेट्रो में लड़ाई-झगड़े या बहस के वीडियो सामने आते रहते हैं। एक ऐसा ही वीडियो चर्चामा में है, जिसमें एक लड़की सीट को लेकर एक शख्स को थप्पड़ लगाती दिख रही है।

दिल्ली मेट्रो में लड़ाई-झगड़े से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। आए दिन कोई बहस, डांस या झगड़े का वीडियो सामने आते रहते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने मेट्रो में सफर कर रहे एक शख्स को थप्पड़ लगा दिया।

सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो घूम रहा है। इसमें सीट को लेकर एक महिला और एक पुरुष के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। देखते ही देखते यह



बहस हाथापाई में तब्दील हो गई। जब महिला ने शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का किसी यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसके बाद से यह वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ghar-kekalesh नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है। इसका कैप्शन है - दिल्ली मेट्रो के अंदर

सीट को लेकर लड़की और अंकल के बीच कलेश। इस वीडियो में मेट्रो में सीट को लेकर एक लड़की और सीट पर बैठे शख्स के बीच तीखी बहस होती दिखाई देती है। फिर अचानक से लड़की उस आदमी को थप्पड़ लगा देती है।

इसके बाद वो शख्स भी खड़ा हो जाता है और लड़की को मारने के लिए हाथ उठाता है, फिर हाथ रोक

टकराव हाथापाई में तब्दील

जैसे-जैसे लड़की का गुस्सा बढ़ता गया, टकराव हाथापाई में तब्दील हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब महिला ने बहस के दौरान पुरुष को थप्पड़ मार दिया। पुरुष तुरंत अपनी सीट से उठा और उसकी ओर बढ़ा, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। इस वीडियो पर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक शख्स ने लिखा है - दिल्ली मेट्रो को ऐसे झगड़ों के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए। ③

लेता है। दोनों के बीच में एक महिला बीच-बचाव करती दिखाई देती है। लड़की लगातार ऊंची आवाज में सामने बैठे शख्स से बहस करती रह जाती है। इसके बाद उस शख्स को आसपास के लोग समझाकर बैठा देते हैं और लड़की आगे बढ़ जाती है। ④



स्नेक शो में सपेरे के हाथ से भागा सांप, टूरिस्ट को डसा

इजिप्ट में के एक रिसोर्ट में हाल ही में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। इजिप्ट के पिरामिड देखने और वहां घूमने आए एक जर्मन टूरिस्ट की विचित्र तरीके से मौत हो गई। वह शख्स रिसोर्ट में सांप के करतब (स्नेक शो) देख रहा था। यह स्नेक शो उसके टूर पैकेज के एक एक्साक्लूसिव ऑफर का हिस्सा था। करतब के दौरान जब सपेरा सांप को टूरिस्ट के नजदीक ले गया तो वह फिसकर उसके पैट में घुस गया और उसे काट लिया। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि एक जर्मन पर्यटक की तब मौत हो गई। ⑤

'राजा शिवाजी' के लिए बिना फीस काम करने की खबरों पर बोले अभिषेक बच्चन- कला में पैसों से ज्यादा जरूरी जुनून

अभिषेक बच्चन इन दिनों 'राजा शिवाजी' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने रितेश देशमुख स्टारर छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी शहाजी भोसले की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को रिलीज हुई 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अभी भी इसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म को रितेश देशमुख ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ लीड रोल भी निभाया है। रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन के अलावा फिल्म में विद्या बालन, जेनेलिया डिसूजा और सलमान खान जैसे स्टार भी हैं। इस बीच फिल्म को लेकर एक चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन सहित कई सितारों ने कोई फीस नहीं ली है। इन खबरों पर अब अभिषेक बच्चन ने खुद प्रतिक्रिया दी है। न्यूजा 18 से बातचीत में अभिषेक बच्चन ने 'राजा शिवाजी' के लिए फीस चार्ज करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 'आजकल रील्स में फैक्ट्स और फिगर्स की बात हो रही है और लोगों को कलाकारों की फीस, वैन की डिमांड जैसी बातों में मजा आ रहा है, लेकिन आखिर में ये एक आर्ट फॉर्म है। ऐसा आर्ट फॉर्म जो दिल से शुरू होता है। जब किसी प्रोजेक्ट पर यकीन सच्चा हो तो पैसी और सुविधाएं कोई मायने नहीं रखतीं। मेरे लिए अभिनय भावनात्मक जुड़ाव है। प्रेरणा ही कला की असली शुरुआत होती है।' अभिषेक बच्चन ने बातचीत के दौरान रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की भी जमकर तारीफ की। स्टार कपल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा- 'आज के समय में फिल्मों में बहुत सारी गणित लगाई जाती है, लेकिन रितेश और जेनेलिया ने साबित कर दिया है कि हर चीज नंबर पर नहीं टिकी होती। उनके लिये ये प्रोजेक्ट बहुत पवित्र था। उन्होंने कभी भी इस फिल्म को किसी प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे फिल्म से कहीं बड़ा और पवित्र मानकर काम किया।' अभिषेक ने फिल्म की भव्यता और चुनौतियों के बारे में बात करते हुए बताया कि मराठी सिनेमा में पहले कभी इतने बड़े स्केल पर कोई फिल्म नहीं बनी है। उन्होंने फिल्म की



भव्यता का बारे में बात करते हुए कहा, 'यूनिट को खुश, सुरक्षित और मोटिवेटेड रखना बहुत मुश्किल काम था। मगर रितेश और जेनेलिया ने इन सभी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला। मुझे सेट पर कभी किसी की भी कोई शिकायत नहीं सुनाई दी। मैं उन्हें अपने परिवार से अलग नहीं मानता। वे बहुत ही प्यारे, डाउन टू अर्थ और भरोसेमंद दोस्त हैं। मैं मुंबई में पला बढ़ा हूँ, इसलिए मैं मराठी से परिचित था, लेकिन स्क्रीन पर पहली बार मराठी बोल रहा था, इसलिए थोड़ा नर्वस था।'

यूपी-बिहार से तीन आरोपी गिरफ्तार शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में बड़ा खुलासा

पश्चिम बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में कोलकाता पुलिस ने यूपी और बिहार से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी राज सिंह को अयोध्या से पकड़ा गया, जबकि दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बिहार के बक्सर से हुई है। तकनीकी निगरानी और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर हुई कार्रवाई के बाद अब मामले में राजनीतिक संरक्षण और पुराने अपराधिक संबंधों की भी जांच तेज हो गई है।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो आरोपी बक्सर बिहार के रहने वाले हैं। जबकि, तीसरा आरोपी यूपी के बलिया का रहने वाला है। लेकिन, वर्तमान यह भी बक्सर में ही रहता है। इनमें से एक आरोपी राज सिंह अयोध्या के नगर कोतवाली क्षेत्र से पकड़ा गया है। हालांकि, इस मामले में जिले की पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। इसके अलावा मयंक मिश्रा और विक्की मौर्या को बक्सर से ही गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मूल रूप से बक्सर के ही रहने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार, मूल रूप से बलिया का रहने वाला राज सिंह लखनऊ की तरफ से लखनऊ-गोरखपुर हाईवे से आ रहा था। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर कोलकाता पुलिस ने इसे नगर कोतवाली क्षेत्र की सीमा में हाईवे से ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, अभी तक इसके संबंध में ठोस साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। पुलिस अधीक्षक नगर चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जानकारी की जा रही है। बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में हुए इस चर्चित हत्याकांड के बाद से वहां की



पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में यूपी समेत कई राज्यों में दबिश दे रही थी। जांच एजेंसियां मोबाइल कॉल डिटेल्, लोकेशन ट्रैकिंग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास कर रही थीं। अब मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस आज दोपहर में प्रेस वार्ता करके गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देगी। सूत्रों के अनुसार, बंगाल पुलिस कई दिनों से राज सिंह की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। रविवार देर रात पुलिस टीम ने उसे अयोध्या में दबोच लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बलिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ले में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। बता दें कि खुद को समाजसेवी कहने वाला राज सिंह जिले के वार्ड नंबर 15 से सभासद का चुनाव भी

लड़ चुका है। राज सिंह के आनंद नगर स्थित आवास पर सोमवार को ताला बंद मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसके परिवार के सदस्य कहीं और चले गए हैं। मोहल्ले में दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है। पड़ोसियों के मुताबिक देर रात कई गाड़ियों के पहुंचने की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद सादे कपड़ों में कुछ लोग मोहल्ले में पहुंचे और पूछताछ करने के बाद वापस लौट गए। हालांकि स्थानीय लोग खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। चर्चा है कि राज सिंह को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पूर्व सदर कोतवाली क्षेत्र में एक अंडा दुकानदार को गोली मारने के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। उस प्रकरण में वह आरोपी रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारी फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं।

चेतन तिवारी गोलीकांड में चौकाने वाला खुलासा हुआ



टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में भाजपा नेता चेतन तिवारी गोलीकांड में चौकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि मुख्य आरोपी वैभव बाजपेई 3 साल पहले तक चेतन का अच्छा दोस्त था। 3 साल पहले चेतन ने अपने नाम के आगे महाराज लिखना शुरू कर दिया। वैभव ने इसका विरोध किया। वैभव का कहना था कि उसके बाबा पुतन बाजपेई को लोगों ने सम्मानपूर्वक महाराज की उपाधि दी थी। वैभव के मना करने के बाद भी चेतन ने अपने नाम के आगे से महाराज लिखना नहीं बंद किया। इससे दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। हालांकि, पुलिस ने वैभव को जेल भेज दिया है। चेतन के परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि वैभव ने चेतन पर एक साल पहले जानलेवा हमला किया था। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसकी रसूख की वजह से मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। इसकी वजह से अब यह घटना हो गई। वैभव ने पुलिस की पूछताछ में बताया- 2023 तक मेरी और चेतन की गहरी दोस्ती थी। नाम के आगे महाराज लिखने के विवाद से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इस दौरान 2024 में चेतन ने मेरे और परिवार के सदस्यों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद से दुश्मनी और गहरी हो गई। वर्चस्व के लिए हम दोनों आपने-सामने हो गए। मेहंदीगंज निवासी सुरेश चंद्र तिवारी के बेटे चेतन तिवारी भाजपा युवा मोर्चा के महानगर कार्यसमिति के सदस्य हैं।

10 बजे के बाद शादी, विवाह में होने वाले तेज शोर को सख्ती से रोकने के निर्देश

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आम लोगों समेत बच्चों व बुजुर्गों को होने वाली असुविधा के मद्देनजर रात 10 बजे के बाद शादी, विवाह व अन्य समारोहों में होने वाले तेज शोर को सख्ती से रोकने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार, पुलिस, नगर निगम और एलडीए को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत समुचित कार्रवाई करने को कहा है। अदालत ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे पाकों, खेल के मैदानों और खुले स्थानों का विवरण तैयार कर उन्हें उत्तर प्रदेश पार्क, खेल मैदान और खुली जगह संरक्षण और विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत तैयार की जाने वाली सरकारी सूची में शामिल करें। कोर्ट ने उन्हें ऐसे स्थानों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने का भी पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी 18 मंडलों के कमिश्नर और सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पाकों, खेल के मैदानों और खुली जगहों का सर्वे करें और उन्हें सरकारी सूची में शामिल करें। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश धर्मपाल यादव की जनहित याचिका पर दिया है। याची ने शहर के जनेश्वर मिश्रा पार्क के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने व्यावसायिक और सामाजिक गतिविधियों के दौरान तेज शोर होने की जन समस्या का भी संज्ञान लिया। कहा कि अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सूचीबद्ध पार्क, खेल के मैदान या खुले स्थानों का



उपयोग, उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता, जिसके लिए उनका उपयोग 1975 में अधिनियम लागू होने से ठीक पहले किया जा रहा था, जब तक कि इसके लिए निर्धारित प्राधिकरण से पूर्व अनुमति न ली जाए। साथ ही अदालत ने खास तौर पर शहर के रिहायशी इलाकों समेत पाकों में आयोजित होने वाले समारोहों में तय सीमा से अधिक शोर होने पर प्रभावी अंकुश लगाने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सीएम योगी की युवाओं से अपील

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

11 मई की तारीख भारत के इतिहास में काफी अहम है। इसी दिन भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस अहम कामयाबी को ध्यान में रखते हुए हर साल 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ऐसे में इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के नाम पाती लिखी है और उनसे बड़ी अपील की है। उन्होंने युवाओं से नवीनतम तकनीक सीखने, नवाचार अपनाने और आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा- "मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह तिथि यू ही नहीं चुनी गई। वर्ष 1998 में इसी दिन पोखरण में 'ऑपरेशन शक्ति' के अंतर्गत भारत ने तीन सफल परमाणु परीक्षण कर विश्व को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा, तकनीकी आत्मविश्वास और राष्ट्रीय सामर्थ्य का बोध

कराया। इसी दिन स्वदेशी विमान 'हंस-3' ने सफल उड़ान भरी, तो स्वदेशी 'त्रिशूल' मिसाइल का परीक्षण भी हुआ। तकनीक केवल विकास का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार है। प्रदेश सरकार इसी मंत्र पर आगे बढ़ रही है।" सीएम योगी ने कहा- "आज तकनीक प्रयोगशाला से निकलकर खेत-खलिहान तक पहुंच गई है। इससे जनजीवन सुगम हुआ है। डीबीटी के माध्यम से पैसे हस्तांतरित हो रहे हैं। आज ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा इसी तकनीक का प्रतिफल है।



भाजपा के रोड शो में तेल की कोई कमी नहीं

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को एक्स पर कहा कि पांच राज्यों के चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जनता का बोझ उठाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। संजय सिंह ने कहा कि चुनाव तक सरकार जनता को भरोसा दिलाती रही कि देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही जनता को तेल, गैस और सोने का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी जाने लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट को भी देशभक्ति से जोड़कर जनता को मानसिक रूप से दबाव में रखने का काम कर रही है, जबकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग खुद ऐशोआराम, विदेशी यात्राओं और भव्य आयोजनों में किसी प्रकार की कटौती नहीं कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं यह कहा कि पिछले दो महीने से सरकार जनता का बोझ उठा रही थी। उन्होंने कहा कि इसका सीधा अर्थ यह है कि जब तक पांच राज्यों के चुनाव चल रहे थे, तब तक सरकार जनता को राहत देने का दिखावा करती रही, लेकिन चुनाव खत्म होते ही अब सरकार कह रही है कि वह जनता का बोझ नहीं उठा सकती।

सेल्समैन की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई

लखनऊ में शराब ठेका के सेल्समैन की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने ठेका खुलने से पहले सेल्समैन से शराब मांगी। सेल्समैन ने मना किया, तो लोहे की रॉड से पीट-पीटकर उसको मार डाला। बीच-बचाव करने आए युवक को भी पीट दिया। घटना का एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज दैनिक भास्कर को मिला है। उसमें दिख



रहा है कि आरोपी रॉड से सेल्समैन को पीटता है। उसके बाद रॉड लहराते हुए फरार हो जाता है। घटना सोमवार सुबह 8:30 बजे मलिहाबाद थाना क्षेत्र के डेडेमऊ गांव में हुई। मृतक की पहचान सैय्यद बाड़ा निवासी अजय जायसवाल उर्फ रिक्कू (35) पुत्र रामऔतार जायसवाल के रूप में हुई। घायल युवक रज्जन का उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान डेडेमऊ गांव निवासी ननक्के कश्यप के रूप में हुई है। वह शराब के ठेके के पास ही रहता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वह लोडर में हेलपर था। जांच में आया है कि आरोपी ने अजय के सिर पर लोहे की रॉड से वार किए। इससे उनका सिर फट गया। वह जमीन पर गिर गए। काफी अधिक खून बह गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक

टीम साक्ष्य जुटा रही है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर देर रात तक अवैध रूप से शराब बेची जाती है। अवैध कैटीन भी संचालित हो रही हैं, जहां रात करीब 12 बजे तक अवैध रूप से शराब की बिक्री होती है। अवैध रूप से शराब बेचने वालों ने ठेके की दीवार में होल बना रखा है। उसमें से ही लोगों को अवैध रूप शराब बेचते हैं। लोगों से अधिक दाम वसूलते हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीणों ने आबकारी विभाग और प्रशासन से इन अवैध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ठेके के 4 पार्टनर हैं। अजय करीब 2 साल से ठेके पर काम करता था। ठेके से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर उसका घर है। वह घर से ही रोज आता-जाता था। सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे वह ठेके के बाहर पहुंचा था। मृतक अजय के परिवार में मां मीरा देवी, पत्नी हेमा जायसवाल, बेटियां खुशी व माही, बेटा कृष्णा और छोटा भाई अमित जायसवाल है। मृतक की पत्नी हेमा ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर दी है।

गंगा की बदली धारा से बढ़ा कटान का खतरा
ड्रेजिंग प्रस्ताव भेजेगी सरकार

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

फतेहपुर चौरासी। गंगा की बदली धारा से कटान की चपेट में आए कालीमिट्टी-शिवराजपुर मार्ग और भविष्य में प्रभावित होने वाले गांवों को बचाने के लिए बांगरमऊ विधायक ने उपजिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान नदी किनारे जाकर स्थिति का जायजा लिया गया। नदी की बदली धारा को परिवर्तित करने के लिए ड्रेजिंग (खुदाई से गंगा में जमी रेत को हटाना) का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने पर सहमति बनी है। फतेहपुर चौरासी के बट्टीपुरवा गांव के पास से गंगा की धारा उन्नाव की तरफ मुड़ गई है। वहीं कहीं-कहीं पर मुख्य धारा उपधारा में बदलकर दो भागों में बंट गई है। इसके चलते पिछले साल बाढ़ के दौरान कालीमिट्टी-शिवराजपुर मार्ग कट गया था। धारा बदलने से पानी आबादी की ओर आने की संभावना बढ़ गई है, जिससे गांवों के लोगों की खेतिहर भूमि व मकानों के गंगा में समाने की आशंका है। रविवार को विधायक श्रीकांत कटियार ने उपजिलाधिकारी बांगरमऊ बृजमोहन शुक्ला, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सुबोध कुमार और अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग दीपक यादव के साथ कालीमिट्टी-शिवराजपुर मार्ग के कटान क्षेत्र का निरीक्षण किया। विधायक



ने अधिकारियों के साथ हिंदूपुर से सरैयाघाट तक का जायजा लिया। इसके बाद चौपाल में प्रधान लक्ष्मीनारायण, रोशन, विजय शंकर यादव, विनोद, रामबाबू, रामशंकर आदि से जानकारी ली। प्रधान व ग्रामीणों ने बताया कि गंगा नदी में गहरी खुदाई कराकर ही धारा को पूर्ववत किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीणों ने गांव हिंदूपुर से कटान तक बचे सुरक्षित मार्ग पर दोनों तरफ बोल्टर (पत्थर) लगाने की भी मांग रखी। मतलबपुर जुलहा से

राधनघाट तक तीन किमी क्षेत्र में कराई जाए खोदाई ग्रामीणों ने बताया कि गंगा में कई जगह रेत के टीले खड़े हो गए हैं। इसलिए पानी सीधे न निकलकर दो धाराओं में बंट गया है। इससे एक धारा उन्नाव की तरफ आ गई है। इससे बचाव के लिए करीब तीन किलोमीटर क्षेत्र में गहरी खुदाई कराकर रेत हटाई जाए। तब कहीं जाकर पानी पुरानी धारा से ही निकल पाएगा। इसके अलावा मार्ग के किनारे पत्थर लगने से कटान की संभावना कम हो

जाएगी। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सुबोध कुमार ने बताया कि गंगा की धारा बदली है। इसलिए ड्रेजिंग कराने पर सहमति बनी है। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर काम कराया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद, पूर्व प्रधान गोविंद पांडेय और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अतुल मिश्रा भी मौजूद रहे।

बाइक अनियंत्रित होकर
कार से टकराई, हादसे में
युवक हुआ गंभीर घायल

हाथरस। थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव रामपुर के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक की बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं, कार सवार लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए हाथरस के बागला जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल युवक की पहचान पवन पुत्र राजपाल निवासी छर्छा, जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पवन अपनी रिश्तेदारी में थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव रामपुर आ रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। फिलहाल चिकित्सकों द्वारा घायल युवक का उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं।

सासनी के गांव
गोहाना में अठारह वां
उर्स का आयोजन सपा
नेता रहे मुख्य अतिथि



सासनी। गांव गोहाना में 18वें उर्स का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के पूर्व हाथरस विधानसभा प्रत्याशी एवं प्रदेश कमिटी सदस्य रामनारायण काके ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उर्स की शुरुआत चारदपोशी के साथ की गई और कुल के साथ मुनाकिव हुआ, कार्यक्रम में रामनारायण काके के पहुंचने पर उर्स इंतजामियां कमिटी के नुमाइंदों और ग्रामीणों ने फूल-मालाएं पहनाकर और समाजवादी पटका पहनाकर जोशीला स्वागत किया। उर्स के सदर राशिद खान फोरमैन और कमिटी के लोगों ने मुख्य अतिथि के साथ आए अन्य गणमान्य लोगों का भी सम्मान किया। इस दौरान पूर्व नगर अध्यक्ष सनी, मास्टर कल्लहसन, वरिष्ठ नेता चमन खान, अनिल कुमार वाष्णीय, विधानसभा अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सेंगर, नेत्रपाल सिंह राजपूत, मैट्रू अल्पसंख्यक सभा के नगर अध्यक्ष अकरम खान, पिंटू दिवाकर और दीपू ठाकुर, नासिर खान, फिरोज खान, चमन खान, लव कुश श्रीवास्तव, मुनीर खान, इसाक खान, रईस खान और कोमल प्रसाद ने आंगतुकों का स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के बृथ अध्यक्ष चमन खान भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम का संचालन नेत्रपाल सिंह राजपूत ने किया। उर्स के दौरान कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में अकीकतमंदों सजदा किया और अमन-ओ-चैन की दुआ मांगी।



लेखपाल का टीन शेड हटाने का वीडियो वायरल
पीड़ित ने लगाए पक्षपात और दबंगई के आरोप

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के पुरवा तहसील में तैनात लेखपाल मनीष यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया सामने आया है। जिसमें लेखपाल एक गरीब व्यक्ति के टीन शेड से बने अस्थायी मकान को हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें पीड़ित पक्ष ने लेखपाल पर बिना नोटिस कार्रवाई करने और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में लेखपाल मनीष यादव एक अस्थायी टीन शेड संरचना को हटाते हुए दिख रहे हैं। मौके पर एक महिला और एक बच्चा भी मौजूद हैं, जो इस कार्रवाई के दौरान लेखपाल का साथ देते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि ग्राम पंचायत की भूमि पर उसका वर्षों पुराना बंगला बना हुआ था, जिसे बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के ध्वस्त कर दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसी भूमि पर अन्य लोगों के पक्के भवन भी बने हुए हैं,

लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसका दावा है कि प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि गरीबों पर कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित ने पुरवा क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन गरीबों की सुनवाई नहीं कर रहा है। उसने यह भी आरोप लगाया कि लेखपाल की क्षेत्र में दबंग छवि है और वह पहले भी रिश्ततखोरी के मामले में निलंबित रह चुका है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन की ओर से प्रतिक्रिया आई है। उपजिलाधिकारी पुरवा प्रमेश श्रीवास्तव ने बताया कि जिस जमीन पर कब्जा हटाया गया, वह ग्राम समाज की भूमि थी और लेखपाल द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि वीडियो और लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाएगी और यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सफाई कर्मचारियों ने नगर पंचायत को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम
लंबित ग्यारह सूत्रीय मांगों पर प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा

सासनी। नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने अपनी ग्यारह सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आक्रोशित और पीड़ित कर्मचारियों ने नगर पंचायत प्रशासन को बहत्तर घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सोमवार को सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने नगर पंचायत प्रशासन के अमरदीप को एक जापन सौंपा। जापन में प्रशासन पर वादाखिलाफी और कर्मचारियों के शोषण का गंभीर आरोप लगाया गया है। जापन में कहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जनता के बीच यह गलत संदेश फैलाया जा रहा है कि कर्मचारियों का सारा बकाया वेतन भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों की अन्य न्यायोचित मांगों पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस के महासचिव अशोक

कुमार ने नगर पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कर्मचारियों के भुगतान को लेकर किए जा रहे दावे पूरी तरह से भ्रामक और गलत हैं। महासचिव ने दावा किया कि एसीपी मद में ही प्रत्येक कर्मचारी का लगभग एक लाख रुपये तक का बकाया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। महासचिव ने प्रशासन से मांग की है कि भ्रामक खबरें फैलाने के बजाय, वर्तमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के वेध बकाये का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। कर्मचारियों ने प्रशासन को अपनी मांगों पर विचार करने के लिए बहत्तर घंटे का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय सीमा के भीतर मांगों का निस्तारण नहीं हुआ, तो समस्त सफाई कर्मचारी काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। इस मौके पर मनोज दिलेर, अशोक चौहान



हरी शंकर, मंजू देवी, दिनेश चौहान, प्रदीप बाल्मीकि, आकाश, सोनू चौहान, साहिल दिलेर, कुलदीप चौहान बंदी दिलेर, आलोक चौहान, नीरज चौहान, शारदा देवी, कुमारी गीता, सहित कई सफाई कर्मचारी मौजूद थे।

बंगाल नतीजों के बाद सपा का नया फॉर्मूला अब पेड़ रणनीतिकार नहीं 'जमीनी प्रहरी' होंगे ताकत

पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों के बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। सपा अब राजनीतिक सलाहकारों और पेड़ वर्कर्स के बजाय बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और "पीडीए प्रहरीयों" पर ज्यादा भरोसा करने की रणनीति बना रही है। पार्टी का फोकस आंदोलन से ज्यादा मतदाता सूची की निगरानी और वोट कटने जैसी संभावित गड़बड़ियों को रोकने पर रहेगा।

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी ने 'अंदरखाने' अपनी चुनावी रणनीति को लेकर गंभीर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी नेतृत्व और रणनीतिकारों का मानना है कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों में सिर्फ राजनीतिक परामर्श फर्मों और पेड़ वर्कर्स पर निर्भर रहने के बजाय जमीनी कार्यकर्ताओं को ज्यादा जिम्मेदारी देना अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। सपा अब अपने पारंपरिक संगठन और कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी को यह भी आशंका है कि चुनाव के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी बड़ा मुद्दा बन सकती है। इसी वजह से आंदोलन और प्रदर्शन से ज्यादा फोकस वोटर लिस्ट की निगरानी पर रखने की तैयारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि भाजपा चुनावी मौके पर मतदाता सूची में फेरबदल या गड़बड़ी करने की कोशिश कर सकती है। इसी वजह से पार्टी अब बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना बना रही है ताकि वोट कटने जैसी स्थितियों को रोका जा सके। पार्टी सूत्रों के अनुसार सपा आगामी चुनावों में मतदाता सूची



के पुनरीक्षण और फॉर्म-7 जैसी प्रक्रियाओं पर विशेष नजर रखेगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की योजना बनाई जा रही है। सपा के भीतर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अपनाई गई रणनीतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ा काम तृणमूल कांग्रेस ने काफी हद तक राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पैक को सौंप दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इस काम के लिए अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को "पीडीए प्रहरी" के रूप में लगाया। सपा नेताओं के मुताबिक दोनों राज्यों के परिणामों में बड़ा अंतर साफ दिखाई दिया। उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची में

तार्किक त्रुटियों और संदिग्ध श्रेणी के आधार पर करीब 27.16 लाख वोट हटाए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में नोटिस पाने वाले करोड़ों मतदाताओं में अपेक्षाकृत बहुत कम नाम हटे। राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर सपा के भीतर यह चर्चा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस को मिले कुल वोटों के अंतर और हटाए गए वोटों के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण रहे। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि यदि मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम नहीं कटते तो चुनावी तस्वीर अलग हो सकती थी। इसी वजह से सपा अब सड़क पर आंदोलन से ज्यादा संगठनात्मक स्तर पर वोटर लिस्ट की निगरानी को प्राथमिकता देना चाहती है। समाजवादी पार्टी के भीतर राजनीतिक परामर्श फर्मों की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में आई-पैक की सलाह पर

तृणमूल कांग्रेस ने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे और बड़ी संख्या में नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। सपा के नेताओं का दावा है कि इन नए चेहरों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसी को देखते हुए पार्टी अब चुनावी रणनीति में पारंपरिक संगठनात्मक ढांचे और अनुभवी कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा करने के पक्ष में दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी अब बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और मतदाता सूची की लगातार निगरानी करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का मानना है कि सिर्फ सोशल मीडिया अभियान या राजनीतिक सलाहकारों के सहारे चुनाव नहीं जीते जा सकते। मजबूत जमीनी नेटवर्क और सक्रिय कार्यकर्ता ही चुनावी सफलता की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं।

मौलाना शहाबुद्दीन ने मुसलमानों को दिया बड़ा संदेश

उत्तर प्रदेश में होने वाले साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिमों को खास संदेश दिया। मौलाना रजवी ने कहा कि आज मैं अपनी कौम से कुछ खास कहना चाहता हूँ, मेरी कौम के लोगों 2027 का जो चुनाव है वह मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहुत हो गया समाजवादी पार्टी को वोट देते हुए, चाहे लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर दिखाकर डराने की कोशिश करते हैं। मौलाना रजवी ने कहा कि सपा के लोग गली-गली मुस्लिम मुहल्लों, गांवों में जाते कि अगर सपा को वोट नहीं दिया तो बीजेपी तुम्हें खा जाएगी। बीजेपी तुम पर जुल्म करेगी। सपा के लोग बीजेपी का खोफ, डर और भय दिखाकर वोट हासिल करते हैं। दूसरी तरफ उनको मुस्लिमों के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह बीजेपी के लोगों के साथ दोस्ती करते हैं। खाते पीते हैं। उठते हैं, बैठते हैं खाना खाते हैं, उसकी सैकड़ों मिसालें। मेरे कौम के लोगों सपा नेता दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वह पीएम मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, दुआ की थी। उन्होंने कहा कि जब योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से लखनऊ बतौर मुख्यमंत्री आए तो अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की और शुभकामनाएं दीं। उनसे कहा कि जब आपका घर तैयार नहीं हो जाता है तब तक आप मेरे घर में चलिए, मेरे घर रहिए। मेरे कौम के लोगों आपने तो नोएडा की तस्वीरें देखीं होंगी कि वहां बीजेपी के नेताओं के साथ सपा के नेता हैं।

बहुजन समाज पार्टी के झंडे के कथित अपमान का मामला सामने आया इटावा में उबाल

जनपद में बहुजन समाज पार्टी (BSP) कार्यकर्ताओं में उस समय भारी आक्रोश फैल गया जब बकेवर थाना क्षेत्र में महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम के दौरान बहुजन समाज पार्टी के झंडे के कथित अपमान का मामला सामने आया। घटना को लेकर बहुजन समाज के लोगों में गहरी नाराजगी व्याप्त है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान लगाए गए बसपा के झंडे को कुछ लोगों ने उतार दिया और कथित रूप से जमीन पर फेंककर उसका अपमान किया। झंडे पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर, बहुजन आंदोलन के संस्थापक कांशीराम तथा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की तस्वीरें लगी होने के कारण मामला और अधिक संवेदनशील हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में रोष फैल गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए बसपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार जाटव के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जापन सौंपा। जापन में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, कठोर कानूनी कार्रवाई तथा पूरे



प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार जाटव ने कहा कि यह केवल पार्टी के झंडे का नहीं बल्कि बहुजन समाज की भावनाओं का भी अपमान है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बहुजन समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की अपील की है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार, नए मंत्रियों ने शपथ

उत्तर प्रदेश में 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम लखनऊ में जन भवन में आयोजित हुआ। इस समारोह में भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री बने। वहीं, अजीत सिंह पाल और सोमेश तोमर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने। इसके अलावा कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह पूरा होने के साथ ही योगी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 60 हो गई है। भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने दोनों विधायकों को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं, अजीत पाल, सोमेश तोमर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ ली। अभी तक यह दोनों योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री थे। इन दोनों मंत्रियों का योगी मंत्रीमंडल में प्रमोशन हुआ है। कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुदेव दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने भी राज्य मंत्री



पद की शपथ ली है। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से लखनऊ स्थित 'जन भवन' में शिष्टाचार भेंट की थी। इस मुलाकात के बाद राज्य में मंत्रिपरिषद विस्तार की खबर पक्की हो गई थी। 'जन भवन' की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें श्री लालचंद राम द्वारा लिखित पुस्तक "भारतीय ज्ञान परंपरा अवधारणा" भेंट की।





आयुष्मान भारत

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

70 वर्ष और उससे अधिक आयु के



सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा वय वंदना योजना का लाभ

योजना की विशेषताएं

- सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार
- मौजूदा बीमारियों का कवरेज पहले दिन से लागू
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग, जिनके पास पहले से कोई निजी बीमा है, वे भी पात्र होंगे
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के राज्य बीमा योजना (ESIC) के लाभार्थी भी पात्र होंगे

कैसे बनवाएं आयुष्मान वय वंदना कार्ड?

प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें

मोबाइल नंबर से लॉगिन करें

सभी आवश्यक जानकारी भरें और e-KYC करें

अपना कार्ड डाउनलोड करें

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर

पात्रता के मापदंड

लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है

आयु का सत्यापन आधार e-KYC के माध्यम से ही पूरा होगा

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत

15 जनवरी से 15 अप्रैल, 2026 तक विशेष अभियान

इस दौरान अपने नजदीकी कैंप पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं

सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची जानने के लिए QR कोड स्कैन करें



अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : 1800-1800-4444/14555

कार्यालय का पता दूसरी और चौथी मंजिल, नवचेतना केंद्र, 10 अग्रोह मार्ग, इन्टरनेशनल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

अब इंटरनेट किस बात का, आज ही ऐप डाउनलोड कर बनावाएं

आयुष्मान वय वंदना कार्ड

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial

CMOUTarpradesh

CMOfficeUP